Jai Hind Defence College, Bhopal

Assignment Questions

LLM 1ST Semester ***Law and Social Transformation In India***

(Compulsory)

नोट : प्रत्येक खंड से पूछे गए प्रश्नों के अंक समान है। प्रत्येक खंड का उत्तर नवीन पृष्ठ से प्रारम्भ करें। समस्त प्रश्नों को अनिवार्यत: हल करें। उत्तर पुस्तिका की संख्या 16 पृष्ठों से अधिक न हो। विद्यार्थी द्धारा स्वंय की हस्तलिपि में उत्तर लिखना अनिवार्य है। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ट प्रिंट निकलकर फिल करें।

Note – All questions carry equal marks. All questions are mandatory and answer limit is 250 words for each question. Start each question from new page. Maximum limit of pages of answer booklet are approximately 16 pages. Answer should be written by the student in his /her own handwriting. The first page of answer sheet needs to be printed and filled accordingly for each subject.

Q1. "सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में विधि के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। भारत में भूमि -सुधारों के संदर्भ में सुसंगत विधि के प्रावधानों तथा निर्णित वादों का उल्लेख कीजिये।

Critically evaluate the importance of Law as an instrument of social change. Cite relevant provisions of Law and decided cases with references to agrarian reforms in India.

Q2. " भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है **" ?** भारतियों को धार्मिक स्वतंत्रता किस सीमा तक प्रदान की गयी है। अपने उत्तर के पक्ष में निर्णीत वादों से कीजिए।

"Indian is a secular State". Examine fully to which extend religious freedom is available to an individual in India. Support your answer with case laws.

Q3. महिला सशक्तिकरण के संबंधित विभिन्न सांविधानिक एवं अन्य विधिक उपबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Critically examine the various constitutional and other legal provisions relating to empowerment of women.

Q4. " बालश्रम का पूर्ण उन्मूलन संभव नहीं है बालश्रम शोषण को न्यूनतमर किया जा सकता है।**"** इस कथन को ध्यान में रखते हुए बालश्रम की भरत में स्थिति,विधिक प्रयासों एवं पुनरुत्थान के लिए स्वेच्छिक संस्थानों के प्रयासों व उनके महत्व पर प्रकाश डालिए।

"Total eradication of child labour is not possible only the exploitation of child labour can be minimized" keeping in view this statement, throw light upon the position of child labour in India. Legislative attempts to protects child labour via action for voluntary para-legal institutions